

दैनिक

घटती घटना

www.ghatatighatana.com

Ghatatighatana11@gmail.com

अम्बिकापुर, वर्ष 20 अंक-306 शनिवार, 07 सितम्बर 2024, पृष्ठ-8 मूल्य 2 रुपये



सरगुजा कलेक्टर किसके दबाव में कर रहे हैं काम

नियम विरुद्ध बुलडोजर कार्यवाही करवाने क्यों मजबूर हुये कलेक्टर बिलास भोसकर

अपील के अधिकार से वंचित कर कुछ घंटों में ही

क्यों उजाड़ दिया आशियाना

पूछकर बताईये कलेक्टर सरगुजा

क्या छापें ?

सरकार ने हक छीना... कलेक्टर ने अपील का अधिकार छीना...

इंकलाब होता रहेगा... इंसाफ तक... कलम बंद का 67 वां दिन

दो अनमोल रतन

एक है संजय, तो दूसरा प्रिंस

इस समय दो अनमोल रतन बने हुए हैं दोनों के ऊपर गंभीर आरोप होने के बावजूद जांच व कार्यवाही में विलंब कुछ ऐसा ही इशारा करता है...



संजय महपात्र, ओएसडी, स्वास्थ्य मंत्री

कौन सी खबर प्रकाशित करें... छत्तीसगढ़ सरकार



प्रिंस जयदेव, प्रभारी डीपीएम, सुरजपुर

आपको जो कमियां दिखाई जा रही हैं वह आपको पसंद नहीं आ रही हैं प्रशासनिक तंत्र में कितनी कमियां हैं यह शायद आपको दिख नहीं रहा और अखबार आपको दिखाना चाह रहा है वह देखना नहीं चाहते ऐसे में क्या प्रकाशित करें यह आप ही तय करें? अखबार जो आपको कमियां दिखा रहा है उस कमियों को आपको दूर करना था पर उन कमियों को दूर करने के बजाय आप अखबार से पत्रकार से संपादक से आपको दिवक्त हो रही फिर आप यह समझिए कि आपसे जनता को कितनी दिवक्त हो रही होगी?

कलमबंद से घटती-घटना के छेही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह



कलेक्टर साहब...! आतंकवादी थे...हत्यारे थे...बलात्कारी थे...इनमें से क्या थे...

कि बिना अपील का मौका दिए बुलडोजर कार्यवाही करना आपकी मजबूरी थी?

-भूपेन्द्र सिंह-
अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2024
(घटती-घटना)। देश में अपने कई बार यह सुना होगा कि खुंखार आतंकवादी या जघन्य हत्याकांड का हत्यारा या बलात्कारी के मामले में बुलडोजर की कार्यवाही एक प्रथा बन गई थी पर यदि ऐसी स्थिति ना हो और फिर भी बुलडोजर की कार्यवाही नियम विरुद्ध तुरीके से कर दी जाए तो फिर सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी या कौन सा कानून व्यवस्था खराब हो रहा था कि किसी अखबार के दफतर व प्रतिष्ठान पर बुलडोजर की कार्यवाही करने की जल्दबाजी की गई? बिना अपील का मौका दिए कार्यवाही करने के लिए आप विवश थे? क्या अखबार के संपादक, पत्रकार आतंकवादी थे...हत्यारे थे...या बलात्कारी थे... या फिर किसी आतंकवादी को अपने कार्यालय में पनाह दे रखी थी कि प्रशासन तुरीके से कर दी जाए तो फिर सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी या कौन सा कानून व्यवस्था खराब हो रहा था कि किसी अखबार के दफतर व प्रतिष्ठान पर बुलडोजर की कार्यवाही करानी पड़ी? आज वही कार्यवाही नासूर बन गई है और चीख-चीख कर हर दिन अखबार फिर भी सवाल पूछ रहा है...कि अब तो आप ही पूछकर बता दीजिए...कि क्या छापे सरगुजा कलेक्टर...और आपने अपील के अधिकार से वंचित क्यों रखा...? आखिर इमानदार छवि वाले...तानाशाह कैसे बन गए?



तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलमबंद अभियान का...67 वां दिन



कलम
बंद...का
67 वां
दिन

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह

कलमबंद से घटती-घटना के सही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...



छत्तीसगढ़ जैसी बुलडोजर कार्यवाही शायद ही देखी होगी..

कार्यवाही किसी आतंकवादी, हत्यारे या बलात्कारी के विरुद्ध नहीं

अखबार के दफ्तर प्रतिष्ठान के विरुद्ध...

कसूर तो बस अखबार के संपादक व पत्रकार का इतना ही था कि वर्तमान सरकार की कमियों को दिखा रहा था

अखबार के दफ्तर पर तो कार्यवाही हो गई पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही से क्यों घबरा रही शासन ?

अखबार के दफ्तर पर कार्यवाही करने से तो शासन नहीं घबराई पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले संजय व प्रिंस पर कार्यवाही करने से घबराहट क्यों ?

जिस अखबार को लोग छोटा अखबार मानते हैं आखिर इस अखबार की खबर से बौखलाहट क्यों होती है ?

सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने प्रतिष्ठान व कार्यालय पर बुलडोजर किसके हुकूम पर चलवाया ?

अखबार के कलम बंद करने से लेकर अखबार के कार्यालय व संपादक के प्रतिष्ठान के टूटने तक की कहानी अपनी जुबानी...

सविधान विरोधी हुई कार्यवाही पर एक नजर... जिसका न्यायालय में जवाब तो सबको देना होगा

- प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो दैनिक घटती-घटना की खबरों की ही देन है उनसे जुड़ी कमियों को अखबार ने जब दिखाया शुरू किया तो उन्हें यह बात रास नहीं आई।
- स्वास्थ्य मंत्री के विभाग में जो हो रहा था उससे उनकी छवि खराब हो रही थी जिसे बताने का काम दैनिक घटती-घटना ने किया तो यह नहीं पता था कि उन्हें बताना कभी महंगा पड़ेगा।
- कमियां दूर करने के बजाय दैनिक घटती-घटना को दबाने के लिए उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए जून 2024 में शासकीय विज्ञापन पर रोक लगाया गया।
- विज्ञापन रोक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दबाव बनाने के फैसले के विरोध में दैनिक घटती-घटना ने 1 जुलाई 2024 से कलम बंद अभियान की शुरुआत की ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमेशा ही स्वतंत्रता के साथ काम कर सके।
- दैनिक घटती-घटना अखबार इस अभियान को सिर्फ अपने लिए शुरू नहीं किया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया...।
- 3 जुलाई 2024 को टीएल मीटिंग में कलेक्टर साहब ने अपने घनिष्ठ प्रिंस जायसवाल के आवेदन को मंगवाया और जांच के लिए आदेशित किया।
- 5 जुलाई 2024 को नमनाकला आरआई ने जांच प्रतिवेदन जांच करके सौंप दिया।
- 10 जुलाई 2024 को आबंटन/व्यवस्थापन समिति के द्वारा हमारे आबंटन/व्यवस्थापन प्रकरण को अपात्र घोषित कर दिया गया।
- 13 जुलाई 2024 को मंत्री जी के प्रतिनिधि मंडल संपादक के कार्यालय पहुंचे बातचीत हुई और चलते बने।
- 19 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक रखी गई और पूर्व सरकार के फ्री होल्ड व 152 प्रतिशत वाली योजना को निरस्त कर दिया गया जिस कारण पूरे प्रदेश के लोगों को नुकसान हुआ जिसका खामियाजा नगरी निकाय चुनाव में वर्तमान सरकार भुगतना पड़ सकता है।
- अखबार के कार्यालय को और संपादक के प्रतिष्ठान को तोड़ने के लिए 19 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक रखी गई।
- 23 जुलाई 2024 को पूर्व सरकार के 152 परसेंट व फ्री होल्ड योजना को निरस्त कर दिया गया...यह आदेश लोगों की जानकारी में 26 जुलाई 2024 को आया और 26 जुलाई को ही बेदखली का नोटिस 23 जुलाई 2024 की तिथि पर दिया गया।
- अखबार के संपादक को बेदखली का नोटिस पिटू शोक के दौरान मिला 26 जुलाई 2024 को शाम 6:45 बजे के बाद मिला और 27 जुलाई 2024 का समय दिया गया बेदखली का।
- पिटू शोक में रहने के बावजूद संपादक ने तत्काल ही 26 जुलाई 2024 को संबंधित अधिकारी को बेदखली में खाली करने के लिए समय मांगा गया पर समय न देकर 28 जुलाई 2024 को सुबह 5:00 बजे प्रशासन कई बुलडोजर व सुरक्षा के साथ पहुंच गया।
- कार्यवाही की एक दिन पहले 27 जुलाई 2024 को रात 10:30 बजे स्वास्थ्य मंत्री के प्रतिनिधि मंडल जिसमें उनके ओएसडी संजय मरकाम सहित चार अन्य लोग संपादक के घर बैठे रहे और मामले पर बात करते रहे।
- स्वास्थ्य मंत्री का प्रतिनिधि मंडल 4:00 तक संपादक के घर बैठ रहा और 5:00 बजे कार्यवाही करने पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया।
- दैनिक घटती-घटना के कलम बंद अभियान को संज्ञान में लेने के बजाय उस अभियान को बंद करने के लिए 28 जुलाई 2024 अखबार के कार्यालय व संपादक के प्रतिष्ठान पर बुलडोजर की कार्यवाही की गई।
- दैनिक घटती-घटना के कलमबंद अभियान के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री और संयुक्त संचालनालय जनसंपर्क के उपसंचालक मयंक श्रीवास्तव से शासकीय विज्ञापन बंद करने को लेकर सवाल पूछा कि आखिर क्या छपे जिससे आपको बुरा ना लगे ?
- यह बात भी सरकार को नागवार गुजरी और सरकार ने और बड़ा कदम उठाया ताकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कुचला जा सके।
- कलमबंद अभियान के तहत 28 दिनों से प्रदेश के जिम्मेदार व प्रदेश की बेहद तरी के लिए जिनके हाथों में कमान है उनसे सवाल किया गया पर वह सवाल को भी बर्दाशत नहीं कर पाए और 28 में दिन दैनिक घटती घटना के संस्थान पर बुलडोजर चलवा दिया।
- बुलडोजर चलवाना भले ही लोकतंत्र को कुचलने के लिए आसान लगा हो पर बुलडोजर चलने की आवाज भी पूरे देश में गूंज गई।
- पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार की तानाशाही दिख गई, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास दिख गया, पर नहीं दिख सकी तो सरकार की संवेदनशीलता सरकार ने यह बात दिया कि उनके अंदर संवेदना बिल्कुल नहीं है।
- जिस समय कार्यवाही की गई वह समय संपादक के घर पर शोक का था पर शोक के समय में सरकार ने कार्यवाही करके हिंदूवादी पार्टी होने के दावे को भी झुल्ला दिया।
- अखबार जो कमियों को दिखा रहा था वह कमी वाकई में सरकार की छवि को खराब कर रही थी सरकार अखबार को खबरों पर संज्ञान लेकर अपनी छवि को बेहतर कर सकती थी।
- उनके मंत्री अपनी छवि को बेहतर कर सकते थे पर अपनी छवि बेहतर करने के बजाय अपनी छवि को और खराब करने का सरकार का प्रयास सरकार के लिए ही गले की फांस बन गई।

दैनिक घटती-घटना संस्थान पर बुलडोजर चलाकर क्या क्रूरतावादी होने का परिचय दिया सरकार ने ?

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा सभाग के दैनिक घटती-घटना अखबार को आखिरकार कलम बंद क्यों करना पड़ा... ?

यह सवाल सभी के जेहन में आ रहा होगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दैनिक घटती-घटना अखबार सदैव ही लोगों के लिए सच्ची खबर प्रकाशित करने का काम करता है, सरकार किसी की भी हो उन्हें कमियां दिखाने का काम करता रहा है, वर्तमान सरकार में कमियों को दिखाने का काम एक बार फिर दैनिक घटती-घटना ने शुरू किया जिसका परिणाम यह मिला कि कार्यालय व प्रतिष्ठान को जमांदोज कर दिया। कलेक्टर सरगुजा को वैसे तो काफी ईमानदार छवि का माना जा रहा था जब वह सरगुजा पहुंचे थे कलेक्टर बनकर लेकिन जैसे ही उनका नाम प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल से जुड़ा वैसे ही उनकी भी छवि अब पाक-साफ नहीं रह गई यह माना जा सकता है। एक फर्जी अहर्ता के आधार पर नौकरी करने के आरोपी के साथ उनकी घनिष्ठता उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। प्रभारी डीपीएम प्रिंस की तो आदत में ही छल और भ्रष्टाचार शुमार है वहीं जैसे ही उसकी शिकायत पर कलेक्टर सरगुजा एक अखबार के विरुद्ध सक्रिय हुए उसे नेस्तनाबूत करने के लिए यह तय हो गया कि कलेक्टर सरगुजा खुद के विवेक से चलने की बजाए एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर काम कर रहे हैं जो फिलहाल जिस नौकरी में है उसके ही जांच की मांग हो रही है और उसके अहर्ता के भी फर्जी होने की बात कही जा रही है भ्रष्टाचार के आरोप तो जो हैं वह हैं ही।

तथा कसूर मात्र फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र व फर्जी डिग्री पर नौकरी करने वाले की खबर प्रकाशित करना था ?

क्या सरकार सच देखना नहीं चाहती या फिर दिख रही कमियों को किसी के दिखाने पर उसे दूर नहीं करना चाहती? किसी अखबार के दफ्तर पर हुई कार्यवाही को लेकर तरह-तरह के सवाल हैं और सवाल हो भी तो क्यों ना हो? क्या वर्तमान सरकार भी फर्जी लोगों को ही संरक्षण देना चाहती है, वास्तविक दिव्यांग सरकार से मिलने वाले लाभ से वंचित हो रहे हैं पर वहीं फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र पर नौकरी पाकर वास्तविक दिव्यांगों के हक को मारा जा रहा, जिसे लेकर दैनिक घटती-घटना ने खबर प्रकाशित कर रहा था, जिसमें संजय मरकाम जो प्रशासनिक राज्य सेवा के अधिकारी हैं साथी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी हैं अब इनके ऊपर आरोप है कि उनकी दिव्यांग प्रमाण-पत्र ही फर्जी है जिसके आधार पर वह डिग्री कलेक्टर बने हुए हैं वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे कहकर घूमने वाले सूरजपुर के प्रभारी डीपीएम प्रिंस जायसवाल जिनकी डिग्री ही फर्जी है, अब इन दोनों के मामले में खबर प्रकाशित की जा रही थी जिसके विरुद्ध शासन को प्रशासन को संज्ञान लेकर जांच करके कार्यवाही करनी थी पर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में घबराहट हुई, पर वहीं उनकी कमियों को प्रकाशित करने वाले अखबार के दफ्तर व प्रतिष्ठान पर कार्यवाही बुलडोजर के द्वारा कर के अपने पाक साफ सरकार बताने में लगे हुए हैं। दोनों ही स्वास्थ्य मंत्री से जुड़े हुए हैं पर स्वास्थ्य मंत्री इन दोनों के मामले में साफ कह रहे हैं कि प्रभारी डीपीएम मेरा कोई भतीजा नहीं है और जांच के लिए बात कही गई है, वहीं उनके ओएसडी के डिग्री फर्जी है यह बात उन्हें पता नहीं थी पर अब पता है तो भी वह कार्यवाही नहीं कर पा रहे, आखिर यह दोनों व्यक्ति कितने प्रभावशील व्यक्ति हैं की स्वास्थ्य मंत्री भी उनके सामने लाचार हैं? पर वहीं इन सब खबरों को प्रकाशित करने वाला अखबार ही कसूरवार हो गया?

तथा भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए ही सरकार केवल सही व्यवहार रखती है.. ?

सरकार की नजर में हमारा कसूर खबरों के मध्यम से कमी दिखाना था, क्या सही में यही वजह थी इसलिए प्रतिष्ठान को नेस्तनाबूत करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि वह सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली सरकार के मंत्रियों के इर्द-गिर्द रहने वाले भ्रष्ट एवं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ वह अभियान चला रहा होता है, जिनकी या तो डिग्री फर्जी है या फिर वह फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, यदि कहा जाए कि केवल गलत लोगों साथ ही भ्रष्टाचार के रास्ते नौकरी में आए भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ही सरकार केवल सही व्यवहार रखती है..? ईमानदार और भ्रष्टाचार विरुद्ध सोच रखने वाले के खिलाफ ही सरकार क्या षड्यंत्र कर रही है...यह भी एक बड़ा सवाल है।

बुलडोजर कार्यवाही हुई भी तो उसके शिकायत पर...जिसकी खबर छप रही थी...शिकायतकर्ता भी कोरिया से दूंद लाए...

दैनिक घटती-घटना अखबार के कार्यालय व प्रतिष्ठान पर कार्यवाही करने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने कैसे शिकायतकर्ता को दूंद कर लाया...वह भी जिसके विरुद्ध लगातार अनियमितताओं खबर छप रही थी...सरगुजा जिले में नहीं मिला...शिकायतकर्ता तो कोरिया से दूंद निकाला गया शिकायतकर्ता...ताकि अखबार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके...और खबर को लेकर दबाव बनाया जा सके...यहां तक कि कलम बंद अभियान को भी बंद किया जा सके।



-भूपेन्द्र सिंह-
अम्बिकापुर, 06 सितंबर 2024
(घटती-घटना)।

पूरे देश में अपने बुलडोजर कार्यवाही के कई मामले देखे व सुने होंगे लगभग सभी मामले ऐसे प्रकरणों में देखने व सुनने को मिले होंगे जो मामले आतंकवादी या हत्यारे या फिर बलात्कारी व भू माफियों से जुड़े होते हैं, जो काफी क्रूरता पूर्वक किसी अपराध को अंजाम देते हैं इसके प्रति

जनता में काफी विरोध होता है और सरकार से न्याय की उम्मीद होती है, ऐसी कार्यवाहियों पर जनता भी सरकार की पीठ थपथपाने का प्रयास करती है, पर इस समय देश के एक छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ की एक बुलडोजर कार्यवाही की बात हो रही है जो अपने आप में एक अजीबोगरीब कार्यवाही कहीं जा सकती है, यह कार्यवाही कहे तो लोकतंत्र के विरुद्ध है कहे तो लोकतंत्र के चौथे

स्तंभ को दबाने के लिए है या कहे तो पावर वाले व्यक्तियों के लिए है जो सच प्रशासन बर्दाशत नहीं कर सकते? यह कार्यवाही आतंकवादी हत्यारे व बलात्कारियों के विरुद्ध नहीं हुई यह कार्यवाही हुई तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ व सविधान के अनुच्छेद 19 के तहत ईमानदारी से खबर प्रकाशित करने वाले अखबार के दफ्तर के विरुद्ध हुई, उसके प्रतिष्ठान के विरुद्ध

जिसमें बिना समय दिए वह अपील के अधिकारों से वंचित करके बुलडोजर कार्यवाही उसे तर्ज पर की गई जिस तर्ज पर आतंकवादियों बलात्कारियों व हथियारों के घरों पर की जाती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद बुलडोजर की पहली कार्यवाही काफी सुविधियों में है और कहे तो काफी विवादों में भी है।



बुलडोजर कार्यवाही से सरकार के चेहरे से हिंदूवादी मुखौटा उतर गया

जिस तरह दैनिक घटती-घटना समाचार-पत्र के विरुद्ध द्वेषवश कार्यवाही सरकार ने की वह कार्यवाही कोई हिंदूवादी सरकार की कार्यवाही नहीं कही जा सकती...? क्योंकि कार्यवाही पीठ पर वार जैसी थी वहीं कार्यवाही तब की गई जब समाचार-पत्र के संपादक गमगीन अवस्था में थे यदि कहा जाए सूतक काल में थे। वैसे कार्यवाही के संदर्भ में यह भी देखने को मिला कि कार्यवाही के लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, यहां तक कि कैबिनेट की बैठक भी उन्हें करनी पड़ी जो यह साबित करने काफी है की सरकार प्रदेश की हिंदूवादी सरकार जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुद को एक बेहतर सरकार बतलाती है वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निम्न स्तरीय निर्णय लेने भी मजबूर हुई क्योंकि भ्रष्टाचारी एक तरफ एक मंत्री का भतीजा भी है और वहीं उसी मंत्री का एक ओएसडी भी और दोनों ही की नौकरी भी फर्जी है डिग्री फर्जी है एक की नौकरी फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के आधार पर लगी है।

खुला पत्र

देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी सवाल...क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार के खिलाफ समाचार लिखना है अपराध ?

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2024 (घटती-घटना)। माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल है...छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है...केन्द्र में भी आपकी पार्टी की सरकार है...पर छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमियां दिखाने से रोकने का भी प्रयास हो रहा है...यह प्रयास कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास है...जहां पर भाजपा सरकार से लोगों को बेहतर करने की उम्मीद होती है तो वहीं पर छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित मंत्री, विधायक बे-लगाम हो चुके हैं...उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ दिख रहे हैं...उनकी कमियों को बताना उन्हें रास नहीं आ रहा इसलिए वह पत्रकार, संपादक का कलम बंद करने का प्रयास कर रहे हैं अब इस पर आप ही संज्ञान ले...और बताएं की संपादक व पत्रकार कौन सी खबर प्रकाशित करें ?

क्या छापें माननीय प्रधानमंत्री जी ?



कलम
बंद...

कलम
बंद...का
67 वां
दिन

कलम
बंद...का
67 वां
दिन



कलम
बंद...

खुला पत्र

भारत में सच्चे पत्रकार को राजनीतिक पार्टियों से खतरा क्यों रहता है?

अम्बिकापुर, 06 सितम्बर 2024 (घटती-घटना)। भारत अपने पत्रकारों को निडर होकर काम करने का स्वतंत्र तरीका प्रदान करने में बहुत पीछे है...इन दिनों...कुछ को छोड़कर...हर दूसरा पत्रकार वही खबर दे रहा है जो सरकार की प्रशंसा करती है...नए चैनल लोगों को सरकार द्वारा की गई गलती से विचलित करने के लिए विभिन्न विषयों पर अनावश्यक बहस दिखाएंगे...इसके कारण, अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो किसी का ध्यान नहीं जाता हैं...दूसरा कारण यह है कि पत्रकार अपने सिद्धांतों और मूल्यों को खो रहे हैं क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि स्थापना के खिलाफ विषयों पर बोलने या लिखने वाले पत्रकारों को धमकी देना, गाली देना और मारना कई अन्य देशों की तरह भारत में भी एक वास्तविकता बन गई है...देश और दुनिया को डरा दिया है...वहीं, पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की घटनाओं ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है...जो पत्रकार देश और उसके आम नागरिकों के लिए लिखे वे मरे या प्रताड़ित हुए सरकारी तंत्रों के द्वारा...!

अब आप ही पूछकर बताईए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर साहब...कि क्या छापें?



कलम
बंद...का
67 वां
दिन

कलम
बंद...



कलम
बंद...का
67 वां
दिन

कलम
बंद...

कलमबंद से घटती-घटना के सहेी पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनारा कुमार सिंह

खुला पत्र

क्या भ्रष्टाचार का मामला वहीं होगा दर्ज जहां होगी भाजपा से इतर दल की सरकार ?

» भ्रष्टाचार की खबरों से दिक्कत...» कमी दिखाओ तो दिक्कत...

» जनता की परेशानियों को दिखाओ तो दिक्कत...

अम्बिकापुर ,06 सितम्बर 2024(घटती-घटना)। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ करें तो क्या करें ? सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने पत्रकार दौड़ रहा पर पत्रकार की दौड़ के पीछे निर्वाचित जनप्रतिनिधि उसकी दौड़ की गति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं,भ्रष्टाचार बढ़ता रहे पर पत्रकार ना दिखाएं क्या यही चाहता है जनप्रतिनिधि या फिर सरकारी तंत्र...

राष्ट्रपति महोदया,आखिर छापें क्या ?



कलम बंद...का 67 वां दिन



कलम बंद...का 67 वां दिन



कलमबंद से घटती-घटना के सही पाठकों,विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह



तुगलकी फरमान के विरुद्ध कलम बंद अभियान का 67 वां दिन

छत्तीसगढ़ सरकार बुलडोजर कार्यवाही
झेलने के बावजूद... इंकलाब होता
रहेगा इन्साफ तक...

क्या छापें कलेक्टर विलास भोसकर जी ?

क्यूं न लिखें सच ?

इमरजेंसी पर बात... हर बात पर आरोप... तो छत्तीसगढ़
में एक तुगलकी फरमान पर आदिवासी अंचल से
विगत 20 वर्षों से प्रकाशित अखबार पर
क्यों किया गया जुर्म... स्पष्टीकरण देना पड़ेगा?

क्यों कलमबंद आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा एक दैनिक अखबार को... ?

कलमबंद से घटती-घटना के सही पाठकों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों को हो रही असुविधा के लिए खेद है...

संपादक :- अविनाश कुमार सिंह